International Journal of Scientific Research in Engineering and Management (IJSREM)
Volume: 10 Issue: 05 | May - 2026 SJIF Rating: 8.659 ISSN: 2582-3930

चुनावी फ्रीबीज़ बनाम राजकोषीय उत्तरदाययत्व: एक आर्थिक ववेचन

Ankit Pandey

Research Scholar

Bundelkhand University, Jhansi

Rajiv Ratna Dwivedi

Associate Professor

Atarra post graduate college, Atarra

सार्वजनिक चचाव से लंबे समय तक गायब रहिे के बाद, "रेर्ड़ी संस्कृनत' क़ी परंपरा कोनर्ड–19 के दौर के बाद पुिः उभऱी, और इसिे तब खासा ध्याि आकनषवत नकया जब प्रधािमंत्री िरेंद्र मोदी िे 2022 में जालौि नजले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसर्े के उद्घाटि के दौराि अपिे भाषण में इसका निक्र नकया। चुिार्ी प्रलोभि बांटिे पर बात करते हुए, प्रधािमंत्री िे कहा,

'आज हमारे देश में उपहार बांटकर र्ोट बटोरिे क़ी संस्कृनत को बढार्ा देिे के नलए हर संभर् प्रयास नकया जा रहा है' [1] ।

1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक क़ी शुरुआत से, जो शुरू में कुछ अलग-थलग कल्याणकाऱी उपायों का एक समूह था, अब राजिीनतक दलों के नलए एक रणिीनतक चुिार्ी हनथयार बि गया है, जो अपिे मतदाता आधार का नर्स्तार करिे और चुिार् ज़ीतिे के नलए इि कायवक्रमों का तेज़ी से उपयोग कर रहे हैं[2]।

जहां एक ओर ये उपहार सामानजक कल्याण क़ी भार्िा से प्रेररत नदखते हैं, र्हीं दूसऱी ओर ये अक्सर राजकोष़ीय अिुशासि को क्षनत पहुंचाते हैं। राज्य सरकारों पर क़िव का बोझ बढता है, बजट असंतुनलत होता है और आर्श्यक संरचिात्मक निर्ेशों क़ी अिदेख़ी होत़ी है। इसके अनतररक्त, यह तकव भ़ी नदया जाता है नक इस तरह क़ी घोषणाएं मतदाताओं क़ी स्वतंत्र इच्छा को प्रभानर्त कर लोकतांनत्रक प्रनक्रया को भ़ी कमजोर कर सकत़ी हैं।

जहां एक ओर ये उपहार सामानजक कल्याण क़ी भार्िा से प्रेररत नदखते हैं, र्हीं दूसऱी ओर ये अक्सर राजकोष़ीय अिुशासि को क्षनत पहुंचाते हैं। राज्य सरकारों पर क़िव का बोझ बढता है, बजट असंतुनलत होता है और आर्श्यक संरचिात्मक निर्ेशों क़ी अिदेख़ी होत़ी है। इसके अनतररक्त, यह तकव भ़ी नदया जाता है नक इस तरह क़ी घोषणाएं मतदाताओं क़ी स्वतंत्र इच्छा को प्रभानर्त कर लोकतांनत्रक प्रनक्रया को भ़ी कमजोर कर सकत़ी हैं। यह शोध पत्र मुख्य रूप से इस आनथवक द्वंद्व पर केंनद्रत है—एक ओर अल्पकानलक लोक-लुभार्ि व्यय, और दूसऱी ओर द़ीघवकानलक राजकोष़ीय उत्तरदानयत्व। शोध का उद्देश्य यह नर्श्लेषण करिा है नक नकस स़ीमा तक चुिार्ी मुफ्त उपहार भारत क़ी सार्वजनिक नर्त्त व्यर्स्था पर बोझ डालते हैं, और यह प्रर्ृनत्त अथवव्यर्स्था के संतुनलत नर्कास के नलए नकस प्रकार खतरा उत्पन्न कर सकत़ी है। इस शोध पत्र का उद्देश्य चुिार्ी फ्ऱीब़ीि क़ी राजिीनत और उसके आनथवक पररणामों क़ी आलोचिात्मक नर्र्ेचिा करिा है। साथ ह़ी यह शोध इस सर्ाल को भ़ी उठाएगा नक क्या भारत जैसे नर्कासश़ील देश में राजकोष़ीय उत्तरदानयत्व के साथ कल्याणकाऱी ि़ीनतयों के ब़ीच कोई संतुलि संभर् है।

आर्थिक लागत

भारत में चुिार् आते-जाते रहते हैं, लेनकि र्े सब्सिड़ी और मुफ्त सुनर्धाओं के रूप में र्ादों का ढेर छोड जाते हैं। ये र्ादे राजिीनतक दलों को नर्नभन्न नर्धायों पर बढत नदलािे में मदद तो करते हैं, लेनकि राज्यों क़ी अथवव्यर्स्था पर भ़ी भाऱी बोझ डालते हैं, जो पहले से ह़ी अपिे पूंज़ीगत व्यय याि़ी भौनतक संपनत्तयों के अनधग्रहण, उन्ननय या रखरखार् पर होिे र्ाले खचव को र्हि करिे के नलए संघषव कर रहे हैं।

“मुफ्त च़ीिें कभ़ी मुफ़्त िहीं होत़ीं... खास तौर पर िुकसािदेह होत़ी हैं सब्सिड़ी जो क़ीमतों को नबगाड देत़ी हैं”। जब राजिीनतक दल ऐस़ी योजिाएँ पेश करते हैं, तो उन्हें मतदाताओं के सामिे नर्त्तपोषण और लेि-देि क़ी शतें स्पष्ट करि़ी चानहए। मुफ्त च़ीजें उत्पादि और संसाधि आर्ंटि को िुकसाि पहुँचात़ी हैं और बड़ी अप्रत्यक्ष लागतें लगात़ी हैं, जैसे नक मुफ्त नबजल़ी के कारण पंजाब में भूजल स्तर में नगरार्ट। उन्होंिे कहा नक ऐस़ी मुफ्त च़ीजें निम्न-गुणर्त्ता र्ाले स्वास्थ्य, नशक्षा,

र्ायु और पाि्ी क़ी क़ीमत पर आत़ी हैं, नजससे सबसे ज़्यादा ि्ुकसाि गऱीबों को होता है।"– **आर्िमा गोयल, सदस्य आरबीआई मौर्िक समर्त।**

र्र्र्न्न राज्ोों के चुनार्ी फ्रीबीज र्ों अथिव्यिस्था के सोंबोंधों पर केस अध्ययन महाराष्ट्र

अिुमािोों से पता चलता है नक राज्य केबजट में घोनषत प्रमुख योजिाओं में से, **'लड़की बहन'** योजिा पर प्रनत र्षव 460 अरब रुपये या 46,000 करोड रुपये (ज़ीएसड़ीप़ी का 1.1 प्रनतशत) खचव होंगे, जो कृनष व्यय के नलए कुल आर्ंटि 356 अरब रुपये से भ़ी ज़्यादा है। इस योजिा के तहत उि मनहलाओं और लडनकयों को 1,500 रुपये क़ी मानसक सहायता द़ी जाएग़ी नजिके पररर्ारों क़ी र्ानषवक आय 2.5 लाख रुपये से कम है। **र्कसानों के र्लए मुफ्त र्बजली योजना** पर प्रनत र्षव 148 अरब रुपये (14,800 करोड रुपये) खचव होंगे। कुल नमलाकर, लोकलुभार्ि योजिाओं के नलए बजट में 960 अरब रुपये या 96,000 करोड रुपये का आर्ंटि नकया गया है। यह ज़ीएसड़ीप़ी का 2.2 प्रनतशत और राज्य के राजस्व का 19 प्रनतशत है [3]।

Emkay ररसचि के अिुसार "महाराष्ट्र में नर्धािसभा चुिार् 2024 के पहले ह़ी राज्य िे अपिे राजस्व और राजकोष़ीय घाटे के लक्ष्य बढा नदए हैं। ज़ीएसड़ीप़ी के नलहाज से सबसे बडा राज्य होिे के बार्जूद, महाराष्ट्र का पूंज़ीगत व्यय और ज़ीएसड़ीप़ी का अिुपात नर्त्त र्षव 19 और नर्त्त र्षव 24 के ब़ीच औसति केर्ल 1.5 प्रनतशत रहा, नजससे यह 19 बडे राज्यों में 16र्ें स्थाि पर रहा।"

तर्मलनाडु

कलैग्नार मगर्लर उररमाई र्थत्तम योजिा के अंतगवत 1.15 करोड पात्र मनहलाओं को ₹1,000 मानसक सहायता देिे का निणवय नलया। यह योजिा मनहला सशक्तीकरण और घरेलू आय में सहयोग देिे के उद्देश्य से शुरू क़ी गई थ़ी। इसके नलए सरकार िे ₹7,000 करोड का बजट आर्ंनटत नकया [4]।

मर्हलाओं और ट्ाोंसजेंडरों के र्लए मुफ्त बस यात्रा: सरकार िे राज्य क़ी सार्वजनिक परर्हि बसों में मनहलाओं, छात्रों और ट्ांसजेंडरों को मुफ्त यात्रा क़ी सुनर्धा जाऱी रख़ी। इस योजिा के अंतगवत र्षव 2023–24 में ₹2,800 करोड क़ी सब्सिड़ी द़ी गई [5]।

र्कसानों के र्लए मुफ्त र्बजली सब्सिडी: तनमलिाडु सरकार िे नकसािोों के कृनष पंप सेट्स के नलए नबजल़ी पर भाऱी सब्सिड़ी द़ी। र्षव 2023–24 में इस योजिा पर ₹14,000 करोड खचव हुए, नजससे ग्राम़ीण कृनष कायों में राहत नमल़ी, लेनकि नबजल़ी बोडव पर राजकोष़ीय दबार् भ़ी बिा [6]।

पोंजाब

पंजाब सरकार िे नर्त्त र्षव 2023–24 में नकसािोों और घरेलू उपभोक्ताओं को **र्बजली र्बल माफी** क़ी सुनर्धा द़ी। बजट अिुमाि के अिुसार, कुल ₹18,276.74 करोड भुगताि नकया गया नजसमें ₹8,881.83 करोड कृनष उपभोग के नलए, ₹6,818.28 करोड घरेलू उपभोक्ताओं के नलए, और ₹2,576.63 करोड औद्योनगक उपभोग-सब्सिड़ी के रूप में शानमल था

(Royal Patiala, 2024)।यह सब्सिड़ी राज्य केराजस्व व्यय का लगभग 19% थी, और पूरे सब्सिड़ी व्यय में इसका नहस्सा बहुत अनधक था [7]।

मुफ्त बस यात्रा (मर्हलाओंकेर्लए): राज्य क़ी बसों में सभ़ी मनहलाओं को मुफ्त यात्रा क़ी सुनर्धा द़ी गई है। र्षव 2023–24 में इस योजिा पर लगभग ₹170–200 करोड खचव हुआ [8]।

स्वास्थ्य बीमा: सरबत सेहत ब़ीमा योजिा: योजिा केतहत 5 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य ब़ीमा नदया गया, जो राज्य केलगभग 42 लाख पररर्ारों को कर्र करता है। 2023–24 में इस पर ₹500 करोड से अनधक खचव हुआ [9]।

र्दल्ली

मुफ्त र्बजली उपिोक्ताओंके र्लए: नदल़्ली सरकार िे नबजल़ी उपभोक्ताओं को 200–400 यूनिट तक मुफ्त नबजल़ी प्रदाि क़ी। इस योजिा का सालािा खचव ₹3,600 करोड तक पहुंच चुका है, जो नदल़्ली क़ी सब्सिड़ी नबल का लगभग 77% नहस्सा बिता है [10]।

मर्हलाओंके र्लए मुफ्त बस यात्रा: नदल़्ली क़ी सार्वजनिक पररर्हि सनर्वस—DTC एर्ं क्लस्टर बसों—में मनहलाओं हेतु मुफ्त यात्रा क़ी व्यर्स्था जाऱी है। र्षव 2023–24 में इस सेर्ा पर सरकार िे लगभग ₹440 करोड खचव नकया [11]।

मुफ्त पानी: सरकार िे पात्र घरेलू पररर्ारों को मुफ्त पाि़ी क़ी सुनर्धा द़ी, नजसके तहत उपलब्ध जािकाऱी केअिुसार ₹500 करोड तक का र्ानषवक खचव इस योजिा पर हुआ [12]।

उत्तर प्रदेि

कृर्ि ट्यूर्बल पर 100% र्बजली र्बल माफी: उत्तर प्रदेश सरकार िे कृनष ट्यूबर्ेल पर नबजल़ी नबल क़ी पूऱी माफ़ी क़ी घोषणा क़ी, नजससे लगभग 1.5 करोड नकसािों को स़ीधा लाभ नमला। यह घोषणा अप्रैल 2023 से प्रभाऱ्ी हुई और बजट में इस योजिा केनलए ₹1,500–1,800 करोड आर्ंनटत नकए गए थे [13]।

मुख्यमोंत्री कन्या सुमोंगला योजना और सामूर्हक र्र्िाह सहायता: राज्य में 'मुख्यमंत्ऱी कन्या सुमंगला योजिा' के तहत लडनकयों के स्वास्थ्य, नशक्षा और नर्र्ाह सहायता के नलए ₹700 करोड आर्ंनटत थे। इसके अलार्ा 'सामूनहक नर्र्ाह सहायता' केतहत गऱीब पररर्ारों क़ी लडनकयों केनर्र्ाह हेतु ₹600 करोड का आर्ंटि नकया गया [14]।

ग्रामीण र्िधिाओंके र्लए र्नरार्ित मर्हला पेंिन: नर्धर्ा मनहलाओं को ₹1,000 प्रनत माह क़ी पेंशि प्रदाि क़ी गई। FY 2023–24 के नलए इसके नलए ₹4,073 करोड का बजट निधावररत नकया गया, नजससे लगभग 31 लाख मनहलाएं लाभाब्न्वित हुईं [15]।

स्वामी र्िर्ेकानन्द युिा सिब्सक्तकरण योजना: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वाम़ी नर्र्ेकािन्द युर्ा सशब्सक्तकरण योजिा के अंतगवत 2023–24 में "मुफ्त टैबलेट और स्माटवफोि" योजिा शुरू क़ी गई। इसका उद्देश्य ग्रेजुएशि, पोस्ट-ग्रेजुएशि, नडप्लोमा और तक़ि़ीक़ी नशक्षा प्राप्त करिे र्ाले छात्रों को नडनजटल नशक्षा पहुँचािे हेतु नि:शुल्क टैबलेट या स्माटवफोि प्रदाि करिा था। सरकार िे इस योजिा के नलए लगभग ₹3,000 करोड का बजट आर्ंनटत नकया और अिुमानित लाभाथी संख्या 1 करोड छात्र रख़ी गई [16]।

िारत के नयंत्रक एिं महालेखा परीक्षक (कैग) के आंकडों से पता चलता है नक 2019-20 में कम होिे के बाद सब्सिड़ी पर राज्य सरकारों का खचव 2020-21 में 12.9 प्रनतशत और 2021-22 में 11.2 प्रनतशत बढा है. इसके अलार्ा, राज्यों के कुल राजस्व व्यय में सब्सिड़ी का अिुपात 2019-20 के 7.8 प्रनतशत से बढकर 2021-22 में 8.2 प्रनतशत हो गया. झारखंड, केरल, ओनडशा, तेलंगािा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों िे नपछले तीि र्षों में सब्सिड़ी में सबसे ज़्यादा र्ृब्धि देखी है. इस बीच गुजरात, पंजाब और छत्तीसगढ जैसे राज्यों िे अपिे कुल राजस्व व्यय का 10 प्रनतशत से अनधक सब्सिड़ी पर खचव नकया [17]।

राज्िार उदाहरण: चुनािी फ्रीबीज़ बनाम राजकोिीय घाटा (2023–24)

राज्य	प्रमुख फ्रीबी योजिाएं	अिुमानित खचव (₹ करोड)*	राजकोषीय घाटा (₹ करोड)	घाटा % GSDP का	स्रोत
पंजाब	मुफ्त नबजली (300 यूनिट), सामानजक पेंशि	~18,000+	~34,784	~5.0%	PRS
नदल्ली	मुफ्त नबजली-पािी, मनहलाओं के नलए मुफ्त बस यात्रा	~11,000	~13,000	~3.5%	TOI / Pioneer
तनमलिाडु	मुफ्त गैस स्टोर्, फैि, नमक्सर, यात्रा सब्सिड़ी	₹25,000+ (कुल योजिाएं)	~30,000+	~3.2–3.4%	PRS / The Hindu
महाराष्ट्र	नकसाि कजव माफ़ी, नर्द्युत सब्सिड़ी	₹30,452	~95501	~2.5	PRS
उत्तर प्रदेश	टैबलेट नर्तरण स्क़ीम, कन्या सुमंगला योजिा आनद।	₹13,000+	~81,000	~3.5–4%	PRS

International Journal of Scientific Research in Engineering and Management (IJSREM)
Volume: 10 Issue: 05 | May - 2026 SJIF Rating: 8.659 ISSN: 2582-3930

सामार्जक कल्याण एिं फ्रीबीज पर केंि केव्यय

भारतीय संनर्धाि केभाग 4 में राज्य केकल्याणकारी स्वरूप को रेखांनकत नकया गया है। िाीनत निदेशक नसांत अपिे िागररकों के नलए आजीनर्का के पयावप्त साधि, समाि नर्कास और संसाधिों का नर्तरण, बच्ों, मनहलाओं, कमजोर और कमजोर र्गों को नर्शेष सुरक्षा, उनचत स्वास्थ्य देखभाल, और अन्य प्रकार की सहायता सुनिनित करिे के साथ गररमापूणव बुनियादी जीर्ि की सुनर्धाओं को देिे के नलए भारतीय सरकार को जर्ाबदेह बिाती हैं। 1960 के दशक िे पहली बार पी डी एस लांच नकया गया। 1995 में नमड डे मील को राष्टर स्तर पर प्रारंभ नकया गया 2013 में कांग्रेस के िेतृत्व र्ाली संयुक्त प्रगनतशील गठबंधि (यूपीए) सरकार िे **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अर्धनियम** पाररत नकया, नजसिे नमड-डे मील या मध्यान्ह भोजि, पीडीएस और बाल नर्कास सेर्ाओं जैसी प्रमुख कल्याणकारी योजिाओं को कािूिी अनधकार नदए. इस कािूि के लाभाथी देश की ग्रामीण आबादी का 75 प्रनतशत और शहरी आबादी का 50 प्रनतशत थे, कुल नमलाकर करीब 800 नमनलयि लोग इसके तहत आते हैं [18]।

2020 में कोरोिा महामारी िे केर्ल र्ेलफेयर स्टेट की महत्वपूणव और अपररहायव भूनमका को रेखांनकत नकया है, क्योंनक एक बड़ी आबादी िे तब अपिी आजीनर्का का साधि खो नदया था और आनथवक नगरार्ट दुनिया के सभी नहस्सों तक दस्तक देिे लगी थी. महामारी द्वारा लाए गए संकट को कम करिे के नलए दुनिया भर की सरकारों द्वारा कल्याणकारी उपाय और सामानजक सुरक्षा पहल की शुरुआत तब की गई थी [19]।

कोनर्ड के दौराि ही आम जिता को राहत देिे के उद्देश्य से **पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना** प्रारंभ की गई। अप्रैल 2020 से नदसंबर 2022 तक योजिा के चरण I-VII में लगभग ₹3.91 लाख करोड की रानश खचव की गई थी, नजसमें 80 करोड से अनधक लोगों को हर महीिे अनतररक्त 5 नकलोग्राम मुफ्त अन्न उपलब्ध कराया गया। केंद्र सरकार िे 1 जिर्री 2024 से नदसंबर 2028 तक के पाँच र्षों के नलए इस योजिा का नर्स्तार नकया। उस अर्नध के नलए अिुमानित कुल खचव लगभग
₹11.80 लाख करोड है [20]। खाद्य मंत्रालय के अिुसार 2023–24 में इस योजिा सनहत कुल खाद्य सब्सिडी: ₹2.05 लाख करोड की रही। जो जीडीपी का 0.75 प्रनतशत के करीब रहा। नकसाि कल्याण पर केंनद्रत **प्रधानमंत्री र्कसान सम्मान नर्ध योजना** भारत सरकार की सबसे बड़ी िकद हस्तांतरण योजिाओं में एक है, नजसका र्ानषवक खचव **₹60,000–61,000 करोड़** है। 2023–24 में यह भारत की GDP का लगभग **0.2%** रहा।

श्रम कल्याण, स्वास्थ्य देखभाल, शहरी नर्कास और जल आपूनतव के क्षेत्रों में सामानजक कल्याण योजिाओं पर राज्यों और केंद्र का संयुक्त खचव, 2020-21 में 65.24 लाख करोड रुपये से बढकर 2021-22 में 71.61 लाख करोड रुपये हो गया – जो लगभग 10 प्रनतशत की बढोतरी थी [21]।

र्िमिि और मुख्य खोजें:

मुफ्त सुर्िधाओं की अत्यर्धक लागत

नबजली सब्सिडी, मनहलाओं के नलए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा, मुफ्त नबजली, कृनष ऋण माफ़ी, मुफ्त लैपटॉप, मुफ्त गैस नसलेंडर और मनहलाओं, बेरोजगार युर्ाओं, नकसािोां और मजदूरों के नलए नर्त्तीय सहायता, 2023 से राज्य चुिार्ोां में दी जािे र्ाली कुछ मुफ्त सुनर्धाएं हैं। कुछ राज्यों के नलए इि मुफ्त सुनर्धाओं की लागत 96,000 करोड रुपये या राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.2 प्रनतशत होिे का अिुमाि है [22]।

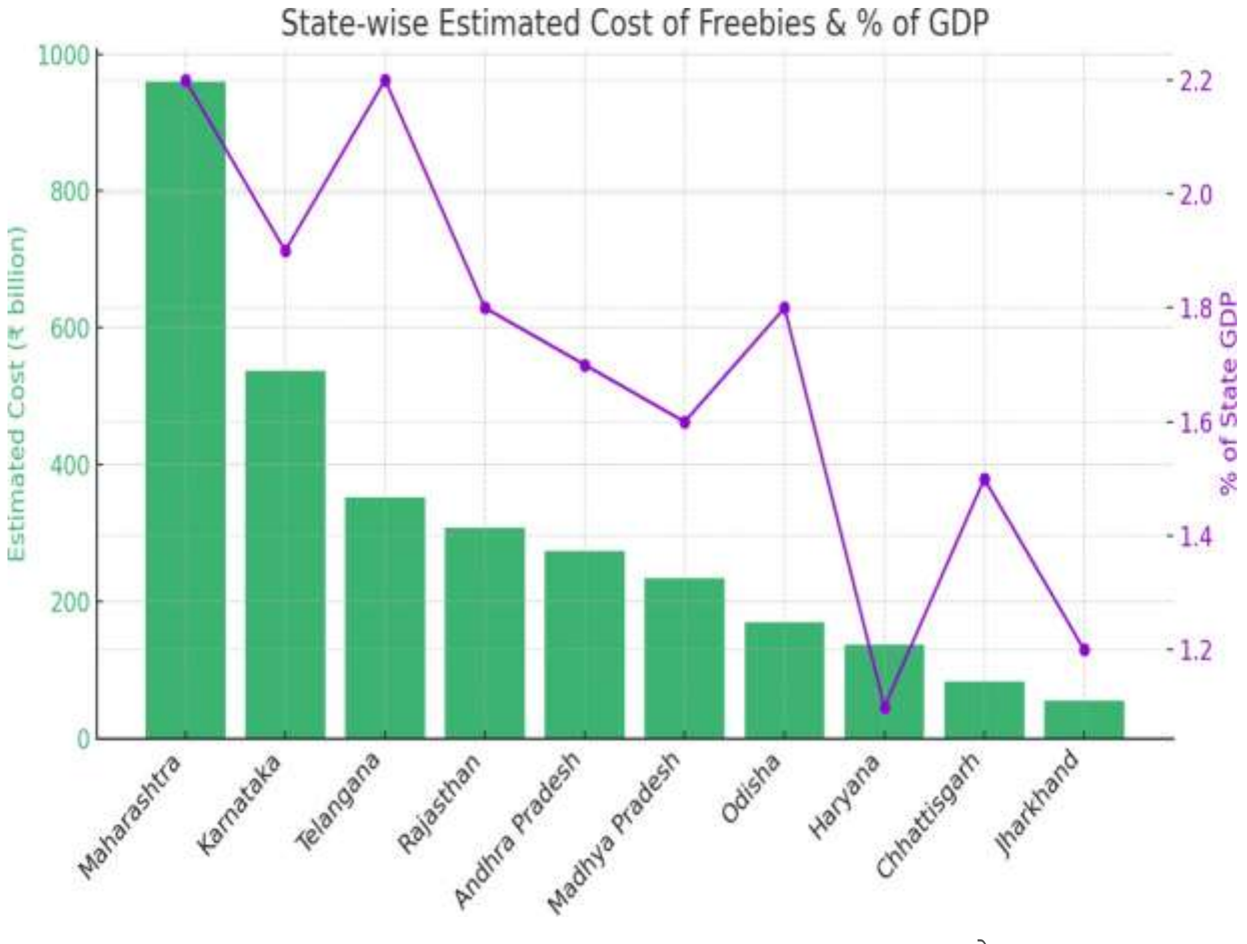

Figure1 (Sources: RBI, State Budget Documents, Emkay Research, 2024) 2023–24 के नलए

‖ ◦ हरे रंग के बार: राज्य द्वारा चुिार्ी मुफ्त उपहारों पर अिुमानित खचव (₹ अरब में)।

‖ ◦ बैंगिी रेखा: उस खचव का राज्य की GDP में प्रनतशत।

राजकोिीय असोंतुलन का कारण

“चुिािी राज्यों में लोकलुभाि खचों क़ी हानलया लहर अब तक चले आ रहे बेहतरीि राजकोषीय संतुलि को नबगाड सकती है। नपछले 20 र्षों में 19 प्रमुख राज्यों के नर्श्लेषण से पता चलता है नक यह कोई िई बात िहीं है। चुिािी र्षों में राज्यों का राजकोषीय घाटा और राजस्व व्यय नपछले र्षव क़ी तुलिा में औसति अनधक रहा है।"– (EMKAY RESEARCH)

इस कारण राज्यों में खचव और प्राब्सप्तयों का अंतराल बढता जा रहा है।

राजकोिीय उत्तरदार्यत्व और बजट प्रबोंधन अर्धर्नयम 2003 के लक्ष्ोों में बाधक

सार्वजनिक ऋण हेतु निधावररत ऋण ज़ीड़ीप़ी अिुपात लक्ष्य 60% से अनधक है।

2024–25 में सामूनहक (केंद्र + राज्य) स्तर पर ऋण ज़ीड़ीप़ी अिुपात 82% से अनधक रहा [23]।

कई राज्य चुिार् के पहले अत्यनधक मुफ्त घोषणाएं करते हैं (जैसे कजवमाफ़ी, फ़्री लैपटॉप, फ़्री यात्रा) जो उिक़ी FRBM स़ीमा (राजकोषीय घाटा 3.5%) से अनधक होत़ी हैं। उदाहरण: पंजाब, आंध्र प्रदेश, राजस्थाि आनद राज्यों का राजकोषीय घाटा 4.5% तक पहुँच गया।

फ्रीबीज और राजकोिीय घाटे के बीच सोंबोंध:

अध्ययि दोिों में सकारात्मक संबंध दशावता है जहाँ राज्य चुिािी मुफ्त सुनर्धाओं पर नजतिा अनधक खचव करते हैं, उिका राजकोषीय घाटा उतिा ह़ी अनधक होता है। सरकारों को चुिािी र्ादों को पूरा करिे के नलए अनधक बजट आर्ंनटत करिा पडता है। इससे राजकोषीय घाटा बढ जाता है। उच् घाटे का अथव है नक राज्य अपि़ी आय से अनधक खचव कर रहे हैं। इससे भनर्ष्य में उि राज्यों क़ी नर्त्तीय संभार्िाओं और आनथवक गारंट़ी के समक्ष गंभ़ीर प्रश्न उठते हैं। यह प्रर्ृनत्त यह भ़ी दशावत़ी है नक राज्य नर्र्ेकपूणव राजकोषीय प्रबंधि के बजाय अल्पकानलक राज़ीनतक लाभ के नलए साल-दर-साल घाटे को बढा रहे हैं।

सुझाि

1. अिसोंरचना और कौिल र्िकास पर खचि

यनद कल्याणकारी कायवक्रमों के नलए नदए गए धि को पुिनिर्वतररत नकया जा सके, तो बेहतर होगा नक इसे बुनियादी ढाँचे के नर्कास, नशक्षा और स्वास्थ्य सेर्ाओं पर खचव नकया जाए, नजिका आनथवक नर्कास से अनधक सीधा संबंध है [24]

इि क्षेत्रों की उपेक्षा से दीघवकानलक आनथवक गनतरोध पैदा हो सकता है, जैसा नक उि राज्यों में हुआ है जो नर्कास-र्धवक क्षेत्रों में निर्ेश नकए नबिा कल्याणकारी कायवक्रमों पर निभवर हैं।

2. फ्रीबीज़ और सब्सिडी के र्गीकरण की स्पष्ट् नीर्त बनाना

सभी लाभकारी योजिाओं को एक समाि िहीं मािा जा सकता। जिनहतकारी आर्श्यक योजिाएँ (जैसे नशक्षा, पोषण, कौशल, स्वास्थ्य सहायता) और "राजिीनतक फ्रीबीज़" (जैसे मुफ्त टीर्ी, टेबलेट, नबजली) में अंतर नकया जाए। बेहतर नक्रयान्वयि हेतु िीनत आयोग या नर्त्त आयोग की तरह एक स्वतंत्र निकाय की स्थापिा की जा सकती है, जो फ्रीबीज़ की प्रकृनत का निधावरण करे।

3. चुनार्ी घोर्णापत्रों में फ्रीबीज घोर्णा से पहले 'राजकोर्ीय प्रिार् ररपोटि' देना अर्निायि

चुिार् घोषणा-पत्र या बजट में नकसी भी फ्री योजिा की घोषणा तभी की जाए जब उसके नर्त्तीय स्रोत और संभानर्त राजकोषीय बोझ का नर्र्रण सार्वजनिक हो। उदाहरण: योजिा की कुल लागत, राजस्व स्रोत, अर्नध, ब्याज/ऋण बोझ का प्रभार् आनद। इसके नलए चुिार् आयोग को जि प्रनतनिनधत्व अनधनियम, 1951 के तहत उनचत शब्सक्त देिे की जािी चानहए तथा फ्रीबीज आधाररत िई धारा का समार्ेश होिा चानहए।

4. लािार्थियों की सही पहचान और लर्क्षत र्ितरण

सीनमत राजकोषीय संसाधिों का उपयोग केर्ल उन्हीं व्यब्सक्तयों पर हो, नजन्हें र्ास्तर् में सहायता की आर्श्यकता है। इसके नलए आधार-आधाररत पहचाि, सामानजक आनथवक जिगणिा डेटा, और JAM (जिधि-आधार-मोबाइल) तंत्र का उपयोग कर योजिाओं को नडनजटली जोडा जा सकता है। आय, भूस्वानमत्व, कर ररकॉडव जैसे मापदंडों के आधार पर अपात्र लोगों को योजिाओं से बाहर करिे हेतु बनहष्करण मािदंड लागू नकया जा सकता है। साथ ही, िकली लाभानथवयों की पहचाि कर उन्हें हटािे, और पात्र लोगों को स्वतः जोडे जािे हेतु ए आई आधाररत नसस्टम नर्कनसत करिे की आर्श्यकता है। इससे सब्सिडी का दुरुपयोग रुकेगा, पारदनशवता बढेगी, और योजिाएं र्ास्तर् में गरीबों तक पहुँचेंगी। पररणामस्वरूप राजकोष पर कम भार पडेगा।

5. फ्रीबीज़ खचि की सीमा तय करना

कई राज्य GDP का 2%–4% तक फ्रीबीज़ पर खचव कर रहे हैं नजससे उिका राजकोषीय घाटा बढ रहा है। अतः आर्श्यक है नक राजकोषीय प्रबंधि और उत्तरदानयत्व अनधनियम, 2003 में संशोधि कर राज्यों के नलए अनधकतम "मुफ्त उपहार व्यय और जीएसडीपी अिुपात" तय हो तथा सीमा के पार जािे पर केंद्रीय सहायता रोकी जा सके।

र्नष्कर्ि

भारत जैसे नर्कासशील लोकतंत्र में चुिार्ी फ्रीबीज का प्रचलि ि केर्ल राजिीनतक प्रनतस्पधाव क़ी प्रकृनत को दशावता है, बल्सल्क यह कल्याणकाऱी राज्य क़ी अर्धारणा और सामानजक न्याय के प्रनत संर्ेदिश़ीलता को भ़ी पररलनक्षत करता है। दरअसल, गऱीबों, नकसािों, मनहलाओं और हानशये पर खडे समुदायों को लनक्षत कर द़ी जािे र्ाल़ी कई योजिाएँ — जैसे मुफ्त राशि, नकसािों को आय समथवि, या स्वास्थ्य ब़ीमा — समाज में व्याप्त नर्षमता को कम करिे तथा न्यूितम ज़ीर्ि स्तर सुनिनित करिे क़ी नदशा में महत्त्वपूणव भूनमका निभात़ी हैं। परंतु जब इन्हें राजिीनतक लाभ के उद्देश्य से गैर तानकवक तऱीके से नबिा नर्त्तीय आकलि, द़ीघवकानलक रणि़ीनत और लनक्षत नर्तरण के लागू नकया जाता है, तो ये योजिाएँ सार्वजनिक नर्त्त क़ी ल्सस्थरता के नलए खतरा बि जात़ी हैं।

इस शोध में यह स्पष्ट हुआ है नक अत्यनधक और अनियंनत्रत फ्रीब़ीज का प्रर्ाह, नर्शेषकर चुिार्ों के दौराि, राजकोष़ीय उत्तरदानयत्व और बजट प्रबंधि अनधनियम द्वारा निधावररत राजकोष़ीय लक्ष्यों (जैसे राजकोष़ीय घाटे क़ी स़ीमा और ऋण-स्तर) को प्राप्त करिे में बाधा बिता है। इससे ि केर्ल बजट में निर्ेशात्मक व्यय (अर्संरचिा, नशक्षा, िर्ाचार आनद) के नलए संसाधि स़ीनमत होते हैं, बल्सल्क यह ऋण और ब्याज के दुष्चक्र में सरकार को धकेल सकता है। इसके अनतररक्त, मुफ्त र्स्तुएँ या सेर्ाएँ यनद समाज में निभवरता क़ी संस्कृनत को बढार्ा देत़ी हैं, तो इससे द़ीघवकाल में कायवश़ीलता और उत्पादकता पर भ़ी प्रनतकूल प्रभार् पडता है तथा सामानजक अकमवण्यता जैस़ी समस्याएं सामिे आ सकत़ी हैं।

हालाँनक यह भ़ी िकारा िहीं जा सकता नक भारत जैसे असमाित-ग्रस्त और नर्नर्धतापूणव देश में कल्याणकाऱी हस्तक्षेप आर्श्यक हैं। इसनलए चुिार्ी र्ादों के रूप में प्रस्तुत योजिाओं का मूल्यांकि 'फ्रीब़ीि बिाम गैर-फ्रीब़ीि' के द्वैध नर्मशव से हटकर नकया जािा चानहए। आर्श्यकता इस बात क़ी है नक सरकारें और ि़ीनत निमावता सामानजक कल्याण और राजकोष़ीय अिुशासि के ब़ीच संतुलि बिाए रखें। इसके नलए ि़ीनत निमावताओं को योजिाओं को राजिीनतक चश्मे से ि देखते हुए कल्याणकाऱी स्वरूप और तानकवकता से देखिा चानहए।

इस प्रकार, भारत को ऐस़ी ि़ीनत अपिाि़ी होग़ी नजसमें लोकलुभार्ि र्ादे और उत्तरदाय़ी शासि, राजकोष़ीय संतुलि एक-दूसरे के पूरक हों ि नक नर्रोधाभास़ी। जब योजिाएँ नर्त्तीय अिुशासि, सामानजक आर्श्यकता और राष्ट्ऱीय नर्कास के नत्रकोण में संतुनलत होकर लागू क़ी जाएंग़ी, तभ़ी हम एक समार्ेश़ी, आत्मनिभवर और स्थाय़ी आनथवक भनर्ष्य क़ी ओर अग्रसर हो सकेंगे।

सोंदिि सूची

1. Mohan, D. (2022, July 27). The Wire. Retrieved from https://thewire.in:https://thewire.in/government/revdi-culture-welfare-narendra-modi
2. Deshpande, R., Tillin, L., & Kailash, K. K. (2019). The BJP's welfare schemes: Did they make a difference in the 2019 elections? Studies in Indian Politics, 7(2), 219-233.
3. Sharma, S. (August 26, 2024) India Today. https://www.indiatoday.in/diu/story/freebies-state-governments-centre-exorbitant-price-gdp-assembly-elections-political-parties-2587996-2024-08-26#google_vignette
4. India Today. (2023, March 20). Tamil Nadu budget 2023: Women to get Rs 1,000 monthly assistance. https://www.indiatoday.in
5. CNBC-TV18. (2023, March 20). Tamil Nadu Budget 2023 Highlights. https://www.cnbctv18.com
6. CNBC-TV18. (2023, March 20). Tamil Nadu Budget 2023 Highlights. https://www.cnbctv18.com
7. https://prsindia.org/budgets/states/punjab-budget-analysis-2024-25
8. Times of India. (2023, February 25). Free bus travel for women in Punjab crosses 3 crore rides. https://timesofindia.indiatimes.com/
9. State Health Agency, Punjab. (2023). Sarbat Sehat Bima Yojana: Annual Report 2023. https://sha.punjab.gov.in/
10. Jeelani, G. (2024, December 9). A decade of AAP govt's free power spending in Delhi. LiveMint. https://www.livemint.com/elections/bjp-congress-follow-aap-freebies-free-power-soar-as-spending-jumps-from-290-cr-to-3-250-cr-11733723587047.html
11. Times of India. (2025, April). Only Delhi women to get 'lifetime' smart card for free bus travel. Times of India. Retrieved from https://www.timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/only-delhi-women-to-get-lifetime-smart-card-for-free-bus-rides-with-smart-cards/articleshow/119941775.cms
12. Times of India. (2025, January). Delhi subsidy bill includes free electricity, water, travel. Times of India. Retrieved from https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/show-me-the-money-test-for-new-govt/articleshow/118033659.cms
13. The Times of India. (2024, March 6). 100% power subsidy for tubewells to UP farmers – a big help ahead of 2024 Lok Sabha polls. Retrieved from https://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/100-power-subsidy-for-tubewells-to-up-farmers-a-big-help-ahead-of-2024-lok-sabha-polls/articleshow/108250871.cms
14. Uttar Pradesh Current Affairs. (2024). Mukhyamantri Kanya Sumangala & Samuhik Vivah Yojana allocations Rs 700 & Rs 600 crore respectively. Retrieved from https://uttarpradeshcurrentaffairs.in/2024-25

15. Uttar Pradesh Current Affairs. (2024). Nirashrit Mahila Pension Yojana allocation Rs 4,073 crore in UP budget 2023–24. Retrieved from https://uttarpradeshcurrentaffairs.in/2024-25

16. Das, A. (2024, December 16). UP Government to provide tablets, smartphones to 2 crore youth – Know complete details inside. Times Bull. Retrieved from https://www.timesbull.com/india-news/up-government-to-provide-tablets-smartphones-to-2-crore-youth-know-complete-details-inside

17. Nivedita, V. "It's Complicated – The Freebie Debate Explained," Business Line, August 26, 2022.

18. PDS Has Scope To Add 10 Million More People: Centre," Hindustan Times, August 19, 2022, https://www.hindustantimes.com/india-news/pds-has-scope-to-add-10-million-more-people-centre-101660849360911.html

19. Covid-19 Has Transformed the Welfare State. Which Changes Will Endure?," The Economist, March 6, 2021, https://www.economist.com/briefing/2021/03/06/covid-19-has-transformed-the-welfare-state-which-changes-will-endure

20. https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1980689&utm_source=chatgpt.com

21. Expenditure on Social Services Rises 9.8 pc to Rs 71.61 lakh crore in FY22: Eco Survey," Economic Times, January 31, 2022.

22. Sharma, S. (2026, Auguat 24) https://www.indiatoday.in/diu/story/freebies-state-governments-centre-exorbitant-price-gdp-assembly-elections-political-parties-2587996-2024-08-26?utm_source=chatgpt.com

23. https://www.worldeconomics.com/Country-Reviews/India/

24. Kumar, A., & Singh, R. (2021). Welfare Policies and Economic Growth in Indian States. Journal of Economic Policy Research, 14(3), 45-67.